भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2327
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

†2327. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है;
(ख) यदि हाँ, तो इन जिलों में स्कूल और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रमुख पहलें की गई हैं;
(ग) सरकारी स्कूलों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (निपुण भारत) और व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना और बहुभाषी शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): दिनांक 29.07.2020 को उदघोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती हुई विकास संबंधी कई अनिवार्यताओं को पूरा करना है। इस नीति में शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और पुनरुद्धार का प्रस्ताव है, जिसमें इसका विनियमन और शासन भी शामिल है, ताकि एक नई प्रणाली सृजित की जा सके जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों का निर्माण करते हुए एसडीजी-4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अनुकूलित हो। एनईपी 2020 में इसके कार्यान्वयन हेतु अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली का भी उल्लेख है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल/उच्चतर शिक्षा संस्थाएं संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं और निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुपालन करते हुए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी मध्य प्रदेश

और उसके देवास एवं शाजापुर जिलों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ख): एनईपी 2020 की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा में कई परिवर्तमारी बदलाव हुए हैं जैसे एनईपी की सिफारिश के साथ केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना का अनुकूल; ग्रेड 2 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने हेतु समझ और संख्याज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); तीन माह के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत एक से अधिक-मोड तक पहुंच को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; ई-बुक्स और ई-सामग्री वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना); 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षण सामग्री के लिए फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस) और जादूई पिटारा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का शुभारंभ; परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) प्रारंभिक, माध्यमिक, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई); विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-साक्षरों को लक्षित करते हुए "न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया (पीएम श्री) योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करना है, जो पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, और एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हैं। ये स्कूल एनईपी 2020 द्वारा निर्देशित सभी घटकों को प्रदर्शित करते हैं।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं जैसे राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ); राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ); स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क; उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत करना; व्यक्तिगत छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत,

अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल अनुप्रयोग प्रक्रिया के माध्यम से द्विपक्षीय निःशुल्क, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम करना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयम मंच का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% क्रेडिट तक की अनुमति उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक समर्थ के माध्यम से प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश; ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रस्तुति करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग; भारत में परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुमति देने के लिए विनियमन; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि।

(ग): एनईपी 2020 की सिफ़ारिश के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को एक समर्पित मिशन "समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में दक्षता हेतु राष्ट्रीय पहल" (निपुण) भारत मिशन शुरू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 तक आवश्यक रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त कर ले। यह मिशन केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना - एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत, सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निपुण-भारत मिशन लागू कर रहे हैं। यह पहली बार है कि 3-6 वर्ष की आयु वर्ग को 5+3+3+4 संरचना में बुनियादी चरण में स्कूल निरंतरता में शामिल किया गया है, जिसमें 3 वर्ष की बालवाटिका और कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।

परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) द्वारा स्थापित किया गया है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य कक्षा 3, 6 और 9 में प्रत्येक शैक्षिक चरण अर्थात बुनियादी, प्रारंभिक और माध्यमिक के अंत में छात्रों की बुनियादी साक्षरता, बुनियादी संख्याज्ञान, भाषा और गणित में अधिगम दक्षताओं का मूल्यांकन करना है। प्रति तीन वर्ष में आयोजित, बीच में वार्षिक राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षणों सहित, नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को हुआ था। परिणाम विशेष रूप से ग्रामीण ग्रेड 3 के छात्रों में बुनियादी कौशल में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित करते हैं, जो निपुण भारत मिशन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। परख एनईपी 2020 के योग्यता-आधारित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अनुकूलित है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सहायता करता है, जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा में एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य छात्रों में रोजगार, उद्यमिता और करियर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों शामिल है और कक्षा VI से VIII तक व्यावसायिक अनुभव प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों को सूचित करके विषय और करियर विकल्प बनाने में मदद मिलती है। कक्षा IX से XII तक, एनएसक्यूएफ-अनुकूलित व्यावसायिक पाठ्यक्रम - माध्यमिक (IX-X) में वैकल्पिक और उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) स्तर पर ऐच्छिक प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, 138 नौकरियाँ अनुमोदित हैं। मार्च 2025 तक; मध्य प्रदेश राज्य के 2282 स्कूलों में 3,84,267 स्कूली छात्रों को कौशल शिक्षा का अनुभव दिया गया है।

(घ) मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के माध्यम से एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, जिसे निष्ठा - समग्र शिक्षा के तहत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल कहा जाता है, शुरू किया है। निष्ठा स्कूल शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। निष्ठा शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाती है जिसका उपयोग छात्रों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु किया जा सकता है। निष्ठा (प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन और ईसीसीई) भारतीय भाषाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल करता है। इसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित शिक्षण-अधिगम में आईसीटी शामिल किए गए पाठ्यक्रमों में से एक है। उल्लेखनीय है कि सभी निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूल शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण - शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन पर समर्पित पाठ्यक्रम मॉड्यूल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जो देशभर में शिक्षा के लिए एक से अधिक-मोड में पहुंच को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई-विद्या पहल को समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से सहयोग दिया गया है और इसे एनसीईआरटी के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। इन पहलों के घटक सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन / प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में अनुकूलित हैं:

दीक्षा- वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफार्म: ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) प्रदान करने के लिए राष्ट्र का डिजिटल अवसंरचना है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, XIवीं और XIIवीं कक्षा के लिए दीक्षा मंच पर कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता घटक शामिल हैं। एनईपी 2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, युवा शिक्षार्थियों और वयस्कों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 117 भारतीय भाषा प्राइमर जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को जगह देने के लिए, 300 से अधिक वर्चुअल लैब बनाए गए हैं और दीक्षा मंच पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की परिकल्पना डिजिटल प्रारूप में 22 भारतीय भाषाओं में विभिन्न स्कूल और उच्चतर शिक्षा विषयों में पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए की गई है।

200 डीटीएच टीवी चैनल : ये चैनल 9 मार्च, 2024 को शुरू किए गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। चैनल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के तहत स्वायत्त निकायों को आवंटित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, 6 दिसंबर, 2024 को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को बढ़ावा देने हेतु एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुरूप और महत्वपूर्ण दर्शकों तक आईएसएल में सीखने-सिखाने की सामग्री की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, एक समर्पित पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल (चैनल सं. 31) के माध्यम से श्रवण बाधित समुदाय के लिए सुलभ शिक्षण संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक समर्पित पहल शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी द्वारा डीटीएच चैनलों और यूट्यूब पर प्रतिदिन एक घंटे की डिजिटल साक्षरता सामग्री प्रसारित की जाती है। स्वयम (स्वयम) प्लेटफ़ॉर्म के एकीकरण के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को मज़बूत किया गया है, जिससे अब कुल कार्यक्रम क्रेडिट का 40% तक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। कुल 388 विश्वविद्यालयों ने स्वयम (स्वयम) को अपनाया है, जिसमें प्रतिवर्ष 5 करोड़ से sअधिक नामांकन और लगभग 10 लाख प्रमाणपत्र शामिल हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्वयम प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो कार्यबल के कौशल विकास और पुनर्कौशल पर केंद्रित है। अब तक 3.26 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

*****